दिसंबर 2020

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

जय किसान 12

पूर्वोदय 4 | वर्चुअल रैली 40 | चौधरी चरण सिंह की जयंती 44 |

R.N.I. No. 68832/97

देश के अन्य सारे धंधे फायदे में हैं लेकिन किसान घाटे में है। जब तक देश का किसान सुखी नहीं होगा तब तक देश संपन्न और महान नहीं बन सकता। 65 प्रतिशत किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि देश के किसान कृषि कार्यों में अपने परिवार की भी मेहनत जोड़ दें तो कृषक जितना घाटे में है, उतना घाटे में कोई नहीं है। यदि किसी किसान परिवार में पांच सदस्य हैं और उनकी मेहनत को 365 दिनों में बांट कर देखा जाए तो मजदूरी बहुत कम पड़ती है।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

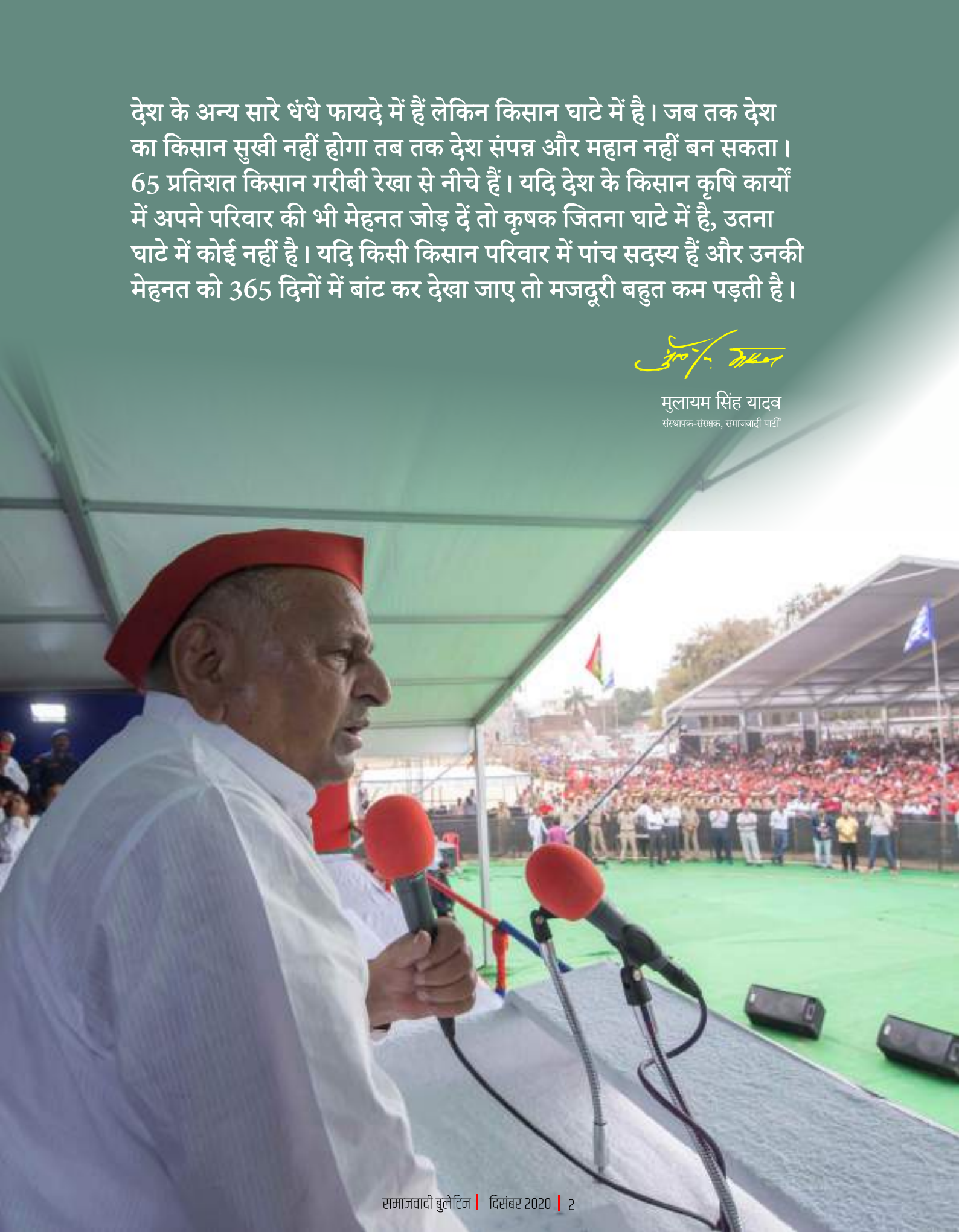

समाजवादी बुलेटिन

दिसंबर 2020

वर्ष 22 | संख्या 02

प्रिय पाठकों,

समाजवादी बुलेटिन का यह नया अंक बदले हुए रंग-रूप और कलेवर में आपके हाथों में है। इसमें समाचार के साथ विचार का संतुलन बनाये रखते हुए आपके लिए पठनीय सामग्री को हर पन्ने पर समेटा गया है। हम निरंतर ऐसी ही सामग्री लेकर आयेंगे। आशा है आपको बुलेटिन का यह नया रूप पसंद आयेगा। आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

किसानों के साथ डटे हैं समाजवादी 20

12 कवर स्टोरी

जय किसान

कार्यक्रम 40

वर्चुअल रैली

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 21 दिसंबर को संतकबीरनगर में हुई वर्चुअल रैली को संबोधित किया। श्री यादव ने रैली के संयोजक श्री सुनील सिंह की गिरफ्तारी को अवैध और निंदनीय बताते हुए कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने से बाज आए।

चौधरी चरण सिंह की जयंती 44

पूर्वोदय 4

पूर्वोदय

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के दिसंबर माह में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों के भ्रमण के दौरान न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं बल्कि आम लोगों में खासा उत्साह दिखा। दो दिवसीय यात्रा पर सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे श्री अखिलेश यादव का रास्ते में अयोध्या, अंबेडकरनगर जनपदों में कई स्थानों पर समाजवादियों व आम लोगों ने जबरदस्त अभिनंदन किया। प्रदेश के पूर्वांचल के महज एक छोटे हिस्से में हुई उनकी दो दिवसीय यात्रा के प्रति ही इतनी उत्सुकता व उत्साह के कारण ही राजनीतिक प्रेक्षक इसे सूर्योदय की तर्ज पर पूर्वोदय की संज्ञा दे रहे हैं।

आजमगढ़

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 13 दिसंबर को लखनऊ से सड़क मार्ग से लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ पहुंच कर रात में ही वे सबसे पहले पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम अहमद के पहाड़पुर स्थित घर पहुंचे व उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता वसीम अहमद का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान 12 दिसंबर को निधन हो गया था।

श्री अखिलेश यादव ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि वसीम अहमद के असामयिक निधन से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। उनकी यह कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वसीम अहमद समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उल्लेखनीय है कि वसीम अहमद श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में बाल विकास पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा एवं ऊर्जा राज्यमंत्री भी रहे हैं।

इसके बाद श्री अखिलेश यादव ने रमेश निषाद एवं निज़ामाबाद नगर पंचायत चेयरमैन प्रेमा यादव के यहां वैवाहिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अगले दिन 14 दिसंबर को श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री दुर्गा यादव के गांव आहोपट्टी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे। वहां मीडियाकर्मियों के सवालों से जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आजमगढ़ के साथ भेदभाव करती है। दोहरे चरित्र के कारण सपा सरकार में शुरू की गई परियोजनाओं को जानबूझ कर अधूरा रखा जा रहा है। इसका खामियाजा यहां के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार जानबूझ कर सपा सरकार में शुरू की गई परियोजनाओं को लटका रही है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के किसानों की ही नहीं पूरे देश के किसानों की हितैषी नहीं है। सरकार ने कृषि कानूनों को पास कर किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया है।

अंबेडकरनगर

आजमगढ़ से लौटते समय आलापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित राम अवध स्मारक महाविद्यालय कसदहा शुकुल बाजार के प्रांगण में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के किसानों की ही नहीं पूरे देश के किसानों की हितैशी नहीं है। सरकार ने कृषि कानूनों को पास

कर किसानों की कमर को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह कानून अहितकर हैं। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के चल रहे धरने को अपना समर्थन देती है और किसानों ही नहीं बेरोजगार नौजवान युवाओं के लिए लड़ी जाने वाली हर लड़ाई में इनके साथ है। आजमगढ़ से अंबेडकरनगर के रास्ते में कई स्थानों पर श्री अखिलेश यादव का जबरदस्त स्वागत हुआ।

अयोध्या

अंबेडकरनगर से चलने के बाद अयोध्या के रास्ते में भी श्री अखिलेश यादव ने अपना काफिला कई स्थानों पर रुकवाकर कार्यकर्ताओं एवं लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। अयोध्या में मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने के बाद मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आऊंगा। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वह उन सभी को मानते हैं। श्री अखिलेश यादव 16 दिसंबर को लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में पहुंचे। जहां जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। क्षेत्र के भौली गांव में एक कार्यक्रम में जाते हुए और वापसी में जानकारी होने पर जगह-जगह स्वत: एकत्रित महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों की भीड़ ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से अभिवादन किया। रैथा रोड़ पर सहभागी शिक्षण केन्द्र में तथा बृज की रसोई के सामने भी श्री यादव का जोरदार अभिनंदन हुआ। स्थानीय लोगों में इतना उत्साह था कि श्री यादव को अपनी कार की गति धीमीकर उनके समीप जाना पड़ा।

प्रेसवार्ता

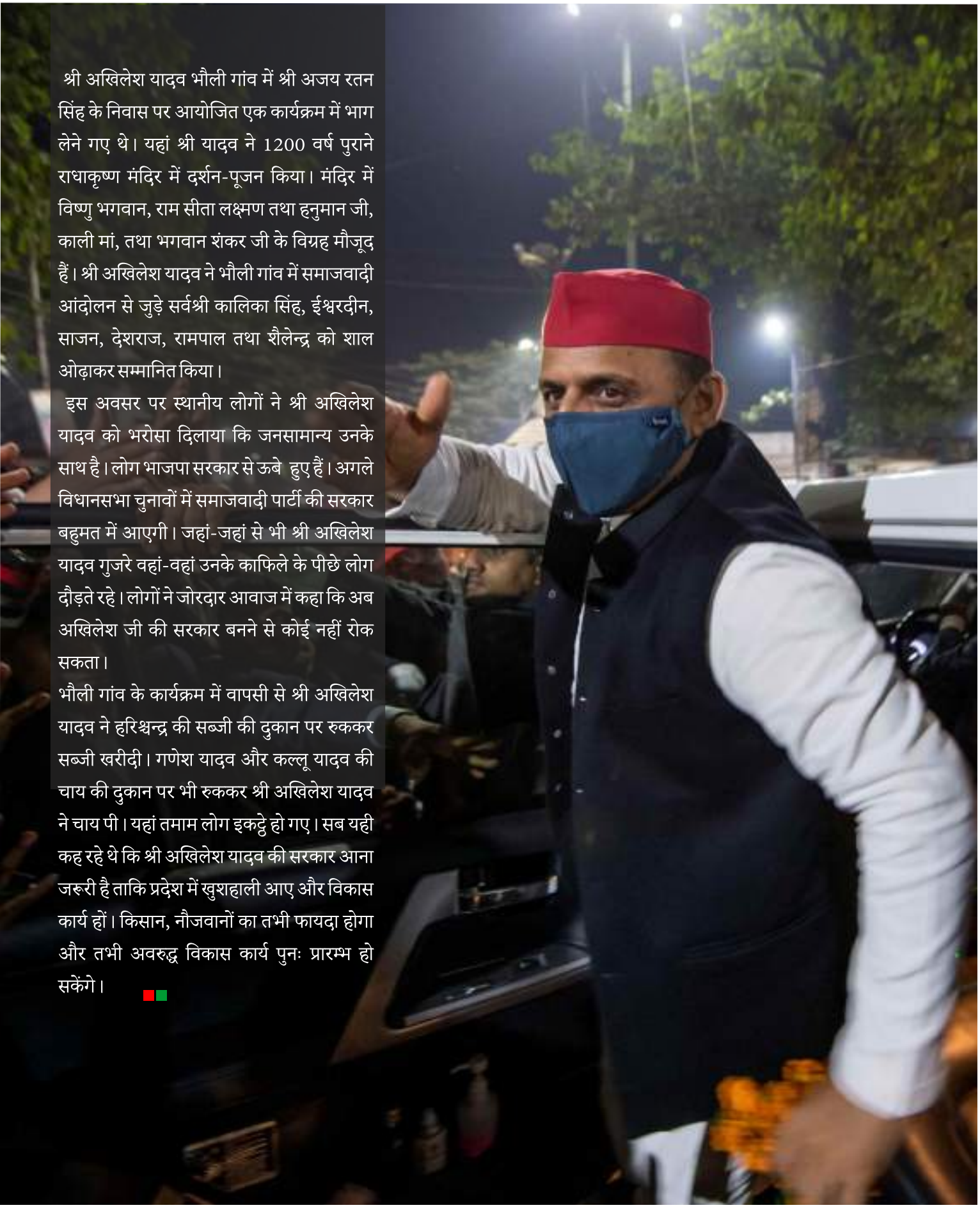

श्री अखिलेश यादव भौली गांव में श्री अजय रतन सिंह के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। यहां श्री यादव ने 1200 वर्ष पुराने राधाकृष्ण मंदिर में दर्शन-पूजन किया। मंदिर में विष्णु भगवान, राम सीता लक्ष्मण तथा हनुमान जी, काली मां, तथा भगवान शंकर जी के विग्रह मौजूद हैं। श्री अखिलेश यादव ने भौली गांव में समाजवादी आंदोलन से जुड़े सर्वश्री कालिका सिंह, ईश्वरदीन, साजन, देशराज, रामपाल तथा शैलेन्द्र को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने श्री अखिलेश यादव को भरोसा दिलाया कि जनसामान्य उनके साथ है। लोग भाजपा सरकार से ऊबे हुए हैं। अगले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में आएगी। जहां-जहां से भी श्री अखिलेश यादव गुजरे वहां-वहां उनके काफिले के पीछे लोग दौड़ते रहे। लोगों ने जोरदार आवाज में कहा कि अब अखिलेश जी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।

भौली गांव के कार्यक्रम में वापसी से श्री अखिलेश यादव ने हरिश्चन्द्र की सब्जी की दुकान पर रुककर सब्जी खरीदी। गणेश यादव और कल्लू यादव की चाय की दुकान पर भी रुककर श्री अखिलेश यादव ने चाय पी। यहां तमाम लोग इकट्ठे हो गए। सब यही कह रहे थे कि श्री अखिलेश यादव की सरकार आना जरूरी है ताकि प्रदेश में खुशहाली आए और विकास कार्य हों। किसान, नौजवानों का तभी फायदा होगा और तभी अवरुद्ध विकास कार्य पुनः प्रारम्भ हो सकेंगे।

पूर्वांचल के उद्यमियों को अखिलेश जी से आस

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 12 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सीडा, सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र जौनपुर के उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों से सम्बंधित उद्यमियों की इस संस्था को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि छोटे, मझोले उद्योग बेकारी दूर करने में मददगार हो सकते हैं लेकिन भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। उद्यमियों द्वारा जोखिम उठाने के बाद भी उन्हें उन्हें अपमान झेलना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उद्यमियों को धमकी देती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। भाजपा सरकार जुल्म भी करती है और कराहने भी नहीं देती है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि विधेयक से लोग बेहाल हैं पर सरकार अपनी हठधर्मी और अहंकार में चूर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। रोज-रोज वह विकास और काम का नाटक करती है, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा काम के अलावा सब कुछ कर सकती है। भाजपा सरकार की साजिशों से सावधान रहना होगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में बेरोजगारी असीमित रूप से बढ़ी है। उद्योग के लिए अत्यावश्यक विद्युत के लिए भाजपा सरकार ने बिजलीघर नहीं बनाए हैं। इस सरकार में एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। छोटे उद्यमियों को सुरक्षा, सम्मान और राहत देने के बजाय भाजपा सरकार कारपोरेट को ही संरक्षण दे रही है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का बड़ा प्रचार हुआ पर उत्तर प्रदेश को क्या मिला? कोई इस प्रदेश में इन हालात में उद्योग लगाने क्यों आएगा?

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए भाजपा सरकार कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। मेडिकल सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे जैसी सड़क नहीं बन सकी।

समाजवादी सरकार में यूपी डायल 100 नम्बर से लोगों का घर बैठे काम हो रहा था, भाजपा सरकार ने उसे 112 नम्बर कर दिया पर यह सेवा काम ही नहीं करती है। ऐसे में अपराध कैसे रूकेंगे?

अखिलेश जी ने कहा कि सन् 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। श्रमिकों की खुशहाली के लिए सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। राज्य में विकास होगा। उन्होंने प्रगतिशील विचार वालों को सजग रहने को कहा क्योंकि भाजपा सरकार छल कपट और नफरत फैलाने में माहिर है। उन्होंने कहा कि इतनी खराब सरकार कभी नहीं आई।

इस अवसर पर इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बृजेश ने संस्था के संबंध में परिचय दिया जबकि उपाध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल ने रिपोर्ट पेश की। श्री बृजेश यादव ने मांग की कि सीडा सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र फ्री होल्ड हो व वहां केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए, ट्रांसफर लेवी चार्ज 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हो, उद्योग लगाने के लिए कैपिटल सब्सिडी देना बहाल किया जाए तथा मुगराबादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर नीलांचल और गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियां रोकने की व्यवस्था हो।

सन् 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि तेजी से औद्योगिक विकास हो सके। श्रमिकों की खुशहाली के लिए सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। राज्य में विकास होगा।

जौनपुर से आए उद्यमियों ने भरोसा जताया कि उन्हें समाजवादी सरकार में ही सम्मान और सुविधाएं मिल सकेंगी उनकी समस्याओं का समय से निदान भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में ही उन्हें सुविधाएं और सम्मान मिला था। सोलर एनर्जी पर टैक्स माफ किया गया था। यूपी में बिजली की खपत ज्यादा है परन्तु पर्याप्त उत्पादन नहीं है। विद्युत दरें दूसरे राज्यों से ज्यादा यूपी में है। उद्यमियों ने कहा कि उन सबको श्री अखिलेश यादव से ही उम्मीद है।

बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनमोहन अग्रवाल, डिवीजनल चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश हवेलिया, पूर्व अध्यक्ष श्री मनीष गोयल, कोषाध्यक्ष श्री शत्रुघन मौर्य, उपाध्यक्ष श्री मो. सुहैल, सचिव डॉ कृष्ण देव प्रजापति एवं श्री अरविन्द कुमार मौर्य, सदस्य सर्वश्री दिनेश तिवारी, मो. जफर, संतोष मौर्य, राकेश गुप्ता, संजय सिंह, दीपचंद्र सोनकर, राजेन्द्र सिंह बिंद तथा पंचदेव बिंद की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

जय किसान

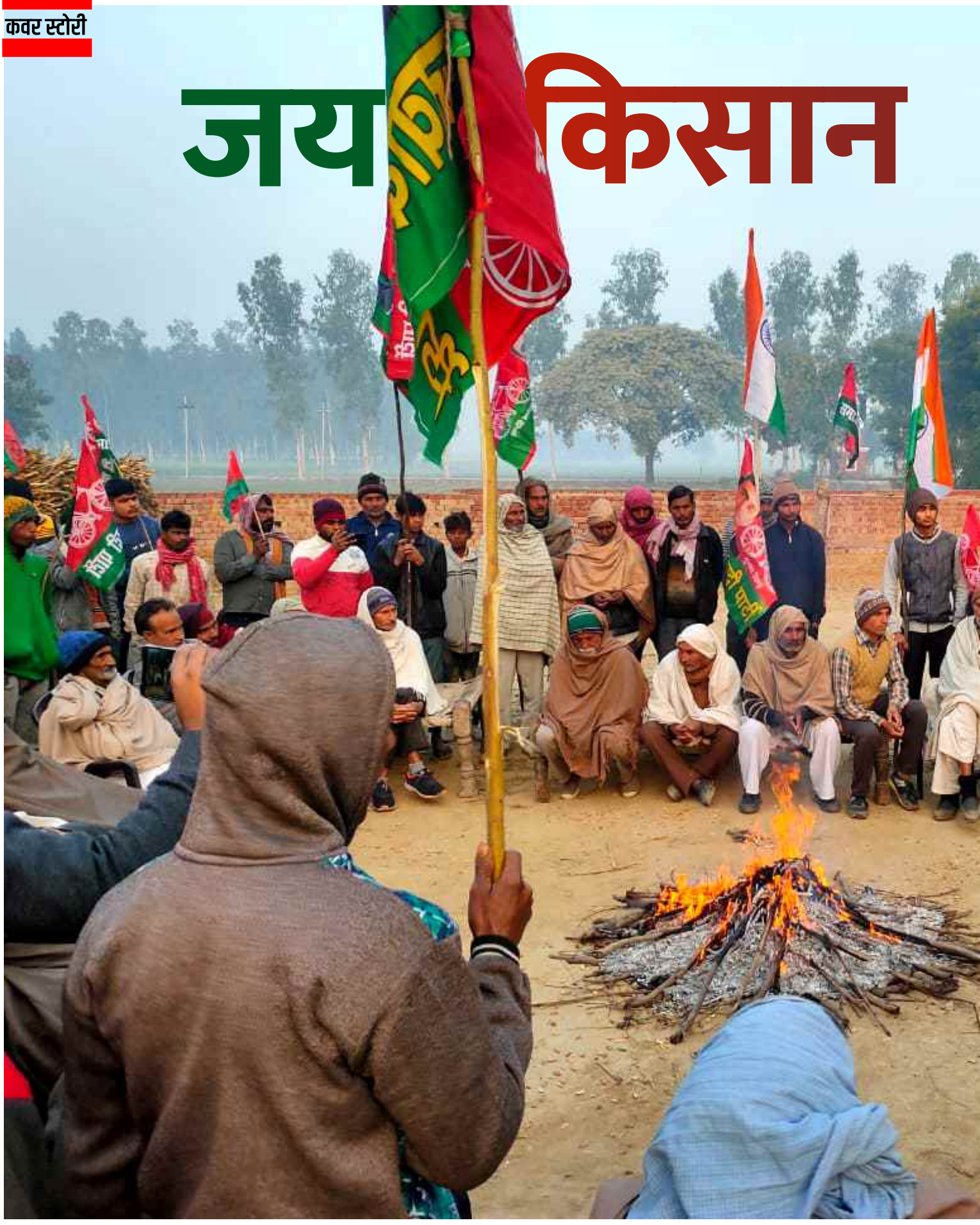

केन्द्र सरकार के तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सीमा पर आंदोलित किसानों के धरना कार्यक्रम के प्रति समर्थन भी निरंतर और व्यापक होता जा रहा है। अन्नदाता के समर्थन में समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर हुई किसान यात्राओं के बाद किसान घेरा कार्यक्रम को भी भारी समर्थन मिल रहा है।

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी द्वारा 25 दिसंबर से पूरे प्रदेश में शुरू किए गए समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम के प्रति आम लोगों, खास तौर पर किसानों में खासा उत्साह है। जनजागरण और जनसंपर्क का यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो रहा है। गांवों में अलाव पर चौपाल लगाकर किसानों के बीच उनकी समस्याओं और भाजपा राज में उनके साथ होने वाले अन्याय पर खुलकर चर्चा की जा रही है।

इसमें किसानों को समाजवादी सरकार में उनके हित में किए गए कामों की भी जानकारी दी जा रही है। समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम में सपा के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी है। अब तक हजारों गांवों

में किसान घेरा कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है। समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम के प्रति जैसे-जैसे जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है उससे बौखलाई राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में पुलिस भेजी जा रही है। बहाना धान खरीद की रिपोर्ट बनाना है जबकि धान की लूट हो चुकी है। सच्चाई यह है कि इसका उद्देश्य गांवों में डर पैदा करना है ताकि किसानों को आंदोलन से डराकर अलग रखा जा सके। किसानों से बात करने के नाम पर उन्हें धमकाया जा रहा है और किसान नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी घरों में नज़रबंद किया जा रहा है।

ऐसा लगता है कि भाजपा का राजनीतिक नेतृत्व अक्षम हो गया है। तभी तो कृषि कानून पर अब पुलिस को बात करने भेजा जा रहा है। धान खरीद की कथित रिपोर्ट पुलिस इकट्ठा कर रही है। दरअसल अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा नेतृत्व किसानों से संवाद नहीं कर पा रहा है। भाजपा का चूंकि किसान-खेती से कभी रिश्ता रहा नहीं इसलिए अन्नदाता का सम्मान करना उसे नहीं आता है। भाजपा लाख झूठ बोले किसान समझ गया है कि उसके फायदे के नाम पर बनाए गए कृषि कानून वस्तुतः छलावा है। जैसे-जैसे भाजपा की जमीन खिसक रही है, वह और भी दमनकारी होती जा रही है लेकिन किसान जाग चुका है, वह भाजपा की साजिशों में अब फंसने वाला नहीं है। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव चाहता है। समाजवादी किसान यात्रा और समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रमों में किसानों की कई लाख की उपस्थिति जताती है कि 2022 में विकास की साइकिल का दौड़ना तय है।

भाजपा का चूंकि किसान-खेती से कभी रिश्ता रहा नहीं इसलिए अन्नदाता का सम्मान करना उसे नहीं आता है। भाजपा लाख झूठ बोले किसान समझ गया है कि उसके फायदे के नाम पर बनाए गए कृषि कानून वस्तुतः छलावा है।

किसान घेरा कार्यक्रम के साथ चौपाल में शामिल किसान स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा है। वे मानते हैं कि समाजवादी सरकार आने पर ही उनको राहत मिलेगी। किसान घेरा कार्यक्रम सुविधानुसार एक दिन में एक या दो गांवों का चयन कर चलाया जा रहा है। किसान घेरा कार्यक्रम में राज्य के ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके तहत सांसद, विधायक, एमएलसी तथा पूर्व मंत्री भागीदारी करते हुए किसानों के बीच चौपाल लगा रहे हैं।

किसान घेरा के अंतर्गत चौपाल में समाजवादी नेता भाजपा राज में किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर बात कर रहे हैं और समाजवादी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। समाजवादी सरकार ने जहां मुफ्त सिंचाई, फसल बीमा, पेंशन, समय से खाद, बीज की उपलब्धता, कामधेनु योजना, मण्डी स्थापना के द्वारा किसानों को खुशहाल बनाने का प्रयास किया था वहीं भाजपा सरकार ने किसानों से खेती का स्वामित्व छीनकर कारपोरेट को सौंपने, मण्डी समाप्ति के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को

नकार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। इन चौपालों में भारत सरकार द्वारा पारित तीनों किसान विरोधी कानून के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले कुप्रभावों और एमएसपी पर भी चर्चा की जा रही है। किसान घेरा में किसान उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और श्री अखिलेश यादव को अपना हितैषी बता रहे हैं। उन्होंने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण चौपाल लगाने में भी कई जगह बाधाएं डालीं। लखनऊ के मोहनलालगंज के विधायक श्री अम्बरीश पुष्कर को नज़रबंद किया गया। करनैलगंज के पूर्व मंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह को भी परेशान किया गया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसान घेरा कार्यक्रम के मौके पर जारी अपने संदेश में कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। भाजपा किसानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा की आर्थिक नीतियां कारपोरेट कारोबारियों के पक्ष में रहती है। उसकी नीतियों में किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम के तहत इन्हीं बातों को गांव-गांव किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आज देश भर में आंदोलित हैं। भाजपा सरकार किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने को तैयार नहीं है। किसानों का खेती पर स्वामित्व भी खतरे में पड़ने वाला है। भाजपा सरकार कांट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों का खेत छीनने की साजिश कर रही है। किसान की फसल बड़े सेठों के मनमर्जी के दामों पर लूटने का प्रबंध किया जा रहा है। भाजपा ने किसानों से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। न तो किसानों को लागत का ड्योढ़ा दाम मिला, नहीं उनकी आय दुगनी होने के आसार हैं। गन्ना किसानों का बकाया अभी तक अदा नहीं हुआ। मंडिया समाप्त की जा रही है। किसानों को समाजवादी सरकार में कर्जमाफी, मुफ्त सिंचाई, खाद, बीज की समय से उपलब्धता, पेंशन और फसल बीमा की सुविधाएं दी गई थी। किसानों को रियायती दर पर बिजली मिलती थी। भाजपा सरकार ने तो किसानों पर बिजली का भार भी बढ़ा दिया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो नए तीन कृषि कानून बनाए हैं उनसे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यह किसान के पक्ष में तो कतई नहीं हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का एक महीना से ऊपर हो गया है। भाजपा अपने प्रिय पूंजीपति मित्रों का समर्थन करते हुए ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जो किसान, मजदूर एवं निम्न मध्यम वर्ग के खिलाफ जाता हैं।

भाजपा सरकार में किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। भाजपा किसानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा की आर्थिक नीतियां कारपोरेट कारोबारियों के पक्ष में रहती है। उसकी नीतियों में किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है।

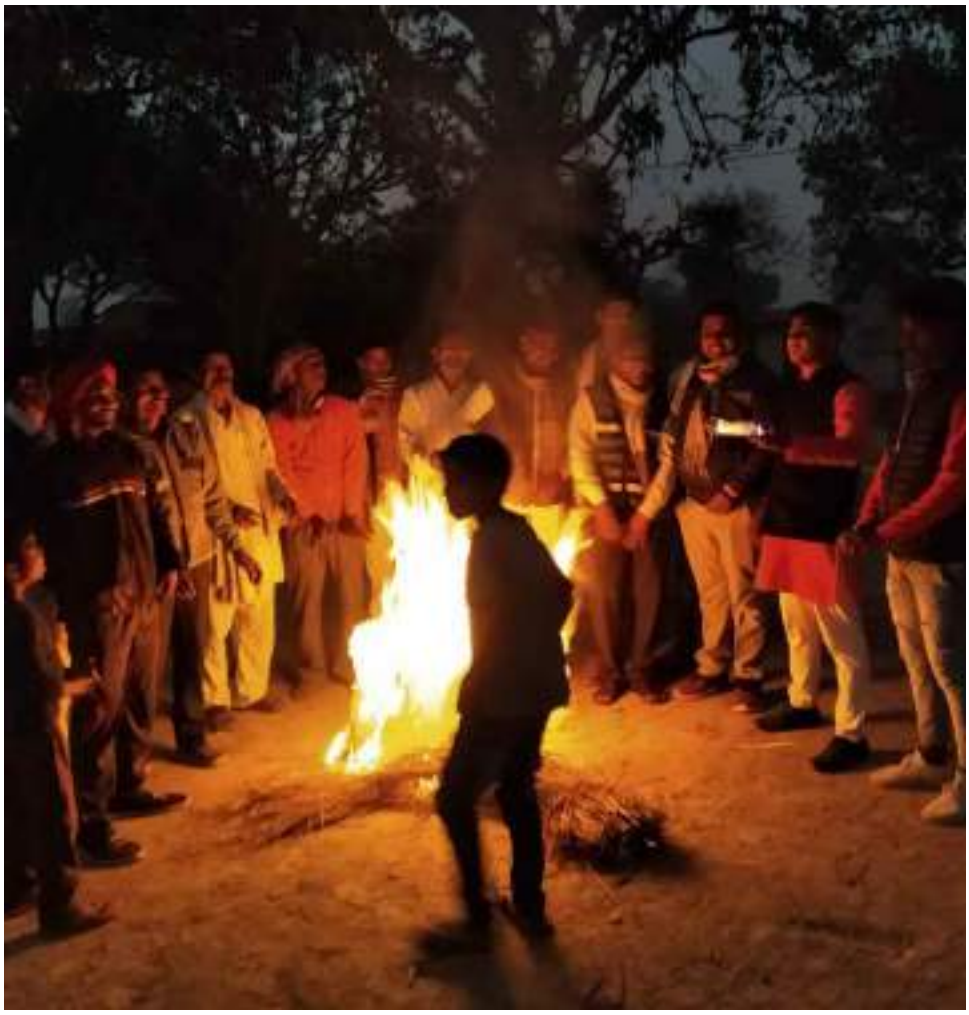

किसान घेरा में लगीं चौपालें

बुलेटिन ब्यूरो

सांसद श्री एस टी हसन ने सिरसवां मुरादाबाद में चौपाल लगाई जबकि श्री रामगोविन्द चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने बड़ागांव बलिया तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने मोहनलालगंज के कपेरा मदारपुर में चौपाल लगाई।

विधायकों में सर्वश्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दुधारा मंचोबा आजमगढ़, लकी यादव ने हरवंशपुर जौनपुर, संग्राम यादव ने नान्हू साह आजमगढ़, संजय गर्ग ने पंजाबी बाग सहारनपुर, मनोज पारस ने स्यालू नंगला बिजनौर, तसलीम अहमद ने अलीपुरा बिजनौर, हाजी इकराम कुरैशी ने लालू वाला मुरादाबाद, मो. रिजवान ने दौलारी मुरादाबाद, इकबाल महमूद ने शाहपुर चमरान सम्भल, श्रीमती पिंकी यादव ने चकरपुर सम्भल में चौपाल लगाई, सर्वश्री नसीर अहमद ने रामपुर शहर, रफीक अंसारी ने घंटाघर मेरठ, महबूब अली ने सहसपुर अलीनगर अमरोहा, नवाब जान ने कोकरझंडी मुरादाबाद, बृजेश कठेरिया ने मनिगांव मैनपुरी, नरेन्द्र वर्मा ने नाथूपुर सीतापुर, सोबरन सिंह यादव ने ककरो मैनपुरी, शरदवीर सिंह ने इमलिया शाहजहांपुर, राकेश प्रताप सिंह ने हरदो अमेठी, अनिल दोहरे ने जनखत कन्नौज, उज्जवल रमण सिंह ने अमीलिया प्रयागराज, अमिताभ बाजपेयी ने घंटाघर चैराहा कानपुर, सुरेश यादव ने असेनी बाराबंकी, यासर शाह ने सोहरवा बहराइच, सुभाष राय ने जमीन सूरजपुर अम्बेडकरनगर, गौरव रावत ने सिसोई बाराबंकी, आशुतोष उपाध्याय ने परोहा देवरिया, नफीस

अहमद ने तिपुरार आईमा आजमगढ़, आलमबदी ने मंझारी आजमगढ़, कल्पनाथ सरोज ने वासूपुर आजमगढ़, वीरेन्द्र कुमार यादव ने जुझारपुर गाजीपुर में किसान घेरा कार्यक्रम किया, प्रभु नारायण यादव ने टाण्डा कला चंदौली, नईमुल हसन ने खानपुर बिजनौर, फहीम इरफान ने जलालपुर मुरादाबाद, ओंकार यादव ने भगतपुर बदायूं, अबरार अहमद ने असुई सुल्तानपुर, अम्बरीष पुष्कर ने हसनपुर लखनऊ, शैलेन्द्र यादव ललई ने सौरईया जौनपुर, नाहिद हसन ने तिसन मसूढ़ा चैदरा शामली में चौपाल लगाई। मैनपुरी में पूर्व सांसद श्री तेज प्रताप यादव ने चौपाल लगाकर किसानों के साथ चर्चा की जबकि लखनऊ में किसान घेरा कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सरोजनीनगर श्री अनुराग यादव ने किसानों के साथ चौपाल लगाई।

पूर्व मंत्रियों में सर्वश्री अवधेश प्रसाद ने तेंघा मिल्कीपुर अयोध्या, शाहिद मंजूर ने लालपुर किठोर मेरठ, अरविंद सिंह गोप ने सूरजगंज रामनगर बाराबंकी, ओमप्रकाश सिंह ने सेवराई देवल जमानिया गाजीपुर, विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह ने सोनउली मोहम्मदपुर तरबगंज गोण्डा, हाजी रियाज अहमद ने परेवा पीलीभीत, फरीद महफूज किदवाई ने दोंदेपुर बाराबंकी, राममूर्ति वर्मा ने अकबरपुर अम्बेडकरनगर, योगेश प्रताप सिंह ने कंजेमऊ गोण्डा, सुरेन्द्र सिंह पटेल ने हरपुर सेवापुरी वाराणसी, रामआसरे विश्वकर्मा ने महमूदपुर चिंतारा आजमगढ़, एसपी यादव ने जैतापुर गैसड़ी बलरामपुर, राजीव कुमार सिंह ने जमीना दरियाबाद, इंद्रजीत सरोज ने निजामपुर मझिगवां नयापुरवा, सरोजनीनगर लखनऊ में चौपाल लगाई।

विधान परिषद के सदस्यों में सर्वश्री रामसुन्दर दास निषाद ने धनौती देवरिया, आशु मलिक ने बरौली बाराबंकी, रामवृक्ष यादव ने सानौटीव कोटवा इलाहाबाद, हीरालाल यादव ने सदपुर पड़िया अम्बेडकरनगर, श्रीमती लीलावती कुशवाहा ने गजियापुर मऊ, उदयवीर सिंह ने बाराखेमपुर बख्शी का तालाब, जितेन्द्र यादव ने इस्माइलपुर बुलंदशहर, दिलीप यादव ने नगलादान सहाय फिरोजाबाद, जसवंत सिंह ने विरदी मिर्जापुर हाथरस, अरविन्द प्रताप यादव ने सिंहपुर गड़िया मैनपुरी, दिलीप उर्फ कल्लू यादव, तुलीचंद पुरवा हरहरा कानपुर, पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन ने मिश्रीपुर कन्नौज, श्रीमती रमा निरंजन ने सरसेड़ा झांसी, वासुदेव यादव ने मुबारकपुर इलाहाबाद, राकेश कुमार गुड्डू ने मुड़ीलपुर आजमगढ़, राम अवध यादव ने सोहरौना कुशीनगर, संतोष यादव सनी मोहम्मदपुर संतकबीरनगर, महफूजुर्रहमान ने मोहम्मदपुर गोण्डा ,सर्वश्री आनंद भदौरिया ने डोली सीतापुर, सुनील सिंह यादव ने पश्चिम गांव उन्नाव, डा॰ राजपाल कश्यप ने भजरेटा हरदोई, संजय लाठर ने भूडवालिया मथुरा और मोहम्मद इमलाख खां ने भिठिया श्रावस्ती, हीरालाल यादव नेसद्दूपुर पडिया अम्बेडकरनगर, राजेश यादव उर्फ राजू ने मोहम्मदपुर बाराबंकी, शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कटांवा सुल्तानपुर, मिस्बाहुउद्दीन ने भलैया हरदोई, शशांक यादव ने वेला तुलसिया खीरी, अमित यादव ने गडिया रंगीन कटरा शाहजहांपुर, परवेज अली ने रसूलपुर गुर्जर अमरोहा, घनश्याम सिंह लोधी ने खैरूल्ला रामपुर, राकेश यादव ने सराय भूपत इटावा, रणविजय सिंह ने गनेशपुर ग्रंट गोण्डा , सर्वश्री मानसिंह यादव ने बैरमपुर पलरा कौशाम्बी,

आशुतोष सिन्हा ने शीरगोवर्धन वाराणसी तथा लाल बिहारी यादव ने विशुनपुर आजमगढ़ में किसानों के बीच चौपाल लगाई।

बदायूं में पूर्व सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव, आगरा में श्री रामजीलाल सुमन पूर्व सांसद तथा श्री रामगोपाल बघेल, अलीगढ़ में पूर्व सांसद श्री विजेन्द्र सिंह, ठाकुर राकेश सिंह पूर्व विधायक तथा श्री हाजी जमीरउल्लाह खान, पूर्व विधायक श्री सगीर अहमद, इटावा में श्री प्रेमदास कठेरिया पूर्व सांसद, श्री गोपाल यादव जिलाध्यक्ष तथा डा॰ भूपेन्द्र दिवाकर, अम्बेडकरनगर में पूर्व सांसद श्री त्रिभुवनदास, कन्नौज में पूर्व विधायक श्री अरविन्द यादव, प्रयागराज में पूर्व विधायक श्री प्रशांत सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश चन्द्र यादव, रामसेवक सिंह पटेल, सीतापुर में पूर्व विधायक श्री अनूप गुप्ता ने चैपाल लगाकर किसानों से वार्ता की।

जौनपुर में पूर्व सांसद तूफानी सरोज, पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव एवं श्री गुलाब सरोज, चंदौली में श्री राम किशुन पूर्व सांसद एवं

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में गांव-खेती और किसान रहे हैं। इस पार्टी के कार्यकर्ता भी ज्यादातर किसान हैं, इसलिए खेती से जुड़े सवालों पर इसकी चिंता स्वाभाविक है। भाजपा सरकार की नीतियां कारपोरेट की पोषक हैं। तीन कृषि कानूनों के जरिए भाजपा सरकार ने किसानों के हितों पर गहरी चोट की है। इससे देश का किसान आंदोलित और आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया गया अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। न तो किसानों को लाभकारी समर्थन मूल्य मिला, नहीं उत्पादन लागत का ड्योढ़ा दाम मिला। भाजपा की प्राथमिकता में गरीब, किसान, नहीं बल्कि कारपोरेट घरानों का हित साधन है। एक ओर वार्ता का ढोंग किया जा रहा है, दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की भी कुचेष्टा हो रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके मंत्रीगण एवं भाजपा के छोटे बड़े सैकड़ों नेता

श्री सत्य नारायण राजभर, भदोही में ही पूर्व विधायक श्री जाहिद बेग एवं श्रीमती मधुबाला पासी तथा जिलाध्यक्ष विघ्न विनायक यादव, गोरखपुर में पूर्व मंत्री श्री राम भुआल निषाद, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर, श्री महावीर एवं श्री यशपाल रावत, कुशीनगर कसया में पूर्व मंत्री श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तथा रामकोला में श्री राघेश्याम सिंह ने समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित किया।

आजमगढ़ में पूर्व सांसद श्री बलिहारी बाबू, बेचई सरोज पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष श्री हवलदार यादव, जयराम पटेल, अखिलेश यादव, सिद्धार्थनगर में श्री आलोक तिवारी पूर्व सांसद, श्री नन्दू चैधरी पूर्व विधायक, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक, बरेली में श्री

किसानों के साथ डटे हैं समाजवादी

कृषि सुधार अधिनियमों के पक्ष में स्वयं प्रचारक बनकर किसानों के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं।

भाजपा सरकार ने किसानों की आवाज को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया है। किसानों पर या उनके समर्थन में खड़े लोगों पर गम्भीर धाराओं में मुकदमें दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा है, किसानों की गिरफ्तारी की है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता किसान ही हैं। समाजवादी पार्टी के इस संघर्ष में किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी दुकानदार, कारोबारी सब साथ हैं क्योंकि कृषि कानूनों का असर सब पर पड़ना है। समाजवादी किसानों के सम्मान और अधिकारों की न केवल दृढ़ समर्थक हैं अपितु उसके लिए संघर्षशील भी हैं। भाजपा सरकार भूले नहीं कि तानाशाही सरकारों को बेदखल करने का जनता और समाजवादियों का गौरवशाली इतिहास रहा है।

भगवतशरण गंगवार, श्री सुल्तान बेग, श्री अताउर्रहमान, मेरठ में श्री राजपाल सिंह जिलाध्यक्ष तथा श्री अतुल प्रधान, बदायूं में पूर्व विधायक श्री प्रेमपाल सिंह ने किसान घेरा कार्यक्रम में ग्रामीणों से वार्ता की। पीलीभीत में पूर्व मंत्री श्री रियाज अहमद ग्राम परेवा वैश्य में तथा एटा में पूर्व विधायक श्री अमित गौरव तथा श्री रामेश्वर सिंह किसानों के बीच पहुंचे। श्री अरविन्द गिरि प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा काकोरी ब्लाक लखनऊ के सिमरामऊ, श्री रामकरन निर्मल प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी ने बख्शी का तालाब रैथा गांव में, श्री दिग्विजय सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा ने सीतापुर में सरैया राजा साहब में किसान घेरा कार्यक्रम में किसानों को समाजवादी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया।

पीलीभीत में पूर्व मंत्री श्री हेमराज वर्मा, श्री प्रीतम राम पूर्व विधायक, श्री नीरज गंगवार पूर्व ब्लाक प्रमुख एवं श्री आनंद यादव पूर्व जिलाध्यक्ष, सोनभद्र में रमेश चंद्र दुबे पूर्व विधायक, विजय सिंह गौंड पूर्व मंत्री, फर्रूखाबाद में श्री कुतबुद्दीन तथा जिलाध्यक्ष श्री नदीम फारूकी, सिद्धार्थनगर में लालजी यादव पूर्व विधायक एवं गिरीश चौरसिया, उग्रसेन सिंह, बलरामपुर में पूर्व मंत्री श्री एस.पी. यादव, पूर्व विधायक श्री जगराम पासवान, पूर्व विधायक श्री मसूद अहमद ने किसान घेरा कार्यक्रम में गांवों में चौपाल लगाई।

प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक श्री नागेन्द्र सिंह मुन्ना ने बाबूगंज अंतू में, अम्बेडकरनगर में विधायक श्री सुभाष राय ने शेखपुर पलिवारी निषाद बहुल गांव में, मऊ में पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र कुमार, धर्म प्रकाश यादव ने ग्राम खुरहट तथा पूर्व विधायक श्री उमेश पाण्डेय ने मधुबन क्षेत्र में, महाराजगंज में डा॰ श्रीकृष्ण भान सिंह सैथवार ने पनियरा सदर में, विनेश कनौजिया, श्री विनोद मणि त्रिपाठी ने फरेंदा में, श्री कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने नौतनवा में, मेरठ में जिलाध्यक्ष श्री राजपाल सिह ने धौलड़ी ग्राम में,अम्बेडकरनगर में पूर्व विधायक श्री जयशंकर पाण्डेय, पूर्व विधायक कुंवर अरूण तथा जिलाध्यक्ष श्री रामसकल यादव ने ग्राम केशवपुर में और आगरा में जिलाध्यक्ष श्री रामगोपाल बघेल के साथ संगठन के अन्य पदाधिकारियों, गौतमबुद्धनगर में श्री वीरसिंह यादव जिलाध्यक्ष ने ग्राम अट्टा, फतेहपुर में फैजाबाद में जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने मवई ब्लाक में वीरेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य जिला पंचायत ने राजापुर बरूआपुर में, श्रावस्ती में पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने क्षेत्र में, कन्नौज में श्री अरविन्द सिंह ने भोजपुर व जमामर्दपुर में, एटा में पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार सिंह ने मौजी ग्राम में, प्रयागराज में श्री संदीप पटेल ,बहराइच में पूर्व विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव , श्री महेन्द्र नाथ यादव जिलाध्यक्ष बस्ती सदर के गांवों में समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच रहे।

फोटो फीचर

तस्वीरों में 'किसान घेरा'

किसान घेरा
- अलाव)

काला कानून
वापस लो

किसानों के लिए समर्पित नेतृत्व

चौधरी चरण सिंह से अखिलेश यादव तक

राजेन्द्र चौधरी

राष्ट्रीय सचिव/पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी

देश का किसान आज उद्वेलित है। अपनी खेती और फसल को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया है। वजह है खेती और फसलों पर बड़े उद्योगपतियों की नजरें। किसान बेबस है। सरकारों की गलत नीतियों से खेती में लागत बढ़ी है। खाद-बीज, कीटनाशक समेत अन्य निवेशों के दाम बढ़े हैं लेकिन फसलों की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ी। इस पर केन्द्र की भाजपा सरकार ने नए कृषि कानूनों से किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का इंतजाम कर दिया है। अब किसान जाए तो कहां जाए। उसकी फसल के साथ जमीन पर भी संकट बढ़ गया है। ऐसे में किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कृषि नीतियां और उनके विचार बेहद प्रासंगिक हो गए हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी के साथ 1979 में गाज़ियाबाद के पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी

23 दिसंबर 1902 को किसान परिवार में पैदा हुए चौधरी चरण सिंह जी मानते थे देश की खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर जाता है। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल होगा। देश की दो तिहाई आबादी अब भी खेती पर निर्भर है। यह विडम्बना है कि किसान कड़ाके की सर्दी में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष में दर्जनों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं लेकिन देश की कारपोरेट समर्थक सरकार हठधर्मी पर अड़ी है। केन्द्र की भाजपा सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार ने अपने चंद कारपोरेट दोस्तों के लाभ के लिए पूरे देश के किसान के जीवन को दांव पर लगा दिया है।

चौधरी चरण सिंह जी को जब भी प्रदेश और देश की सरकार में मौका मिला तब-तब उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लिए। उन्होंने केन्द्रीय वित्तमंत्री रहते जो बजट संसद में प्रस्तुत किया, उसमें सरकार के बजट का 70 फीसदी हिस्सा गांवों के लिए दिया। उन्हीं के सिद्धांतों और विचारों पर चलकर समाजवादी सरकारों ने किसानों को राहत देने के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकारों ने किसानों के लिए तमाम क्रांतिकारी कदम उठाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों का खास ख्याल रखा। उन्होंने बजट का 75 फीसदी गांवों पर खर्च किया। किसानों के लिए मंडी क्षेत्र को मजबूत किया। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा किसानों को मिलता था।

समाजवादी सरकारों ने गरीबों और किसानों की भलाई के लिए किसान दुर्घटना बीमा योजना, कर्जमाफी, मुफ्त सिंचाई, खाद-बीज पर अनुदान जैसी योजनाओं से किसानों की खेती की लागत को कम किया। चौधरी चरण सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए श्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की नीतियां बनाते समय खेती-गांव और किसान को हमेशा प्राथमिकता दी। किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो, फसल का उचित मूल्य मिले और फसल समय पर मंडी पहुंचे इसको लेकर समाजवादी सरकारें पूरी व्यवस्था करती थीं। लेकिन गैर समाजवादी सरकारों में किसान शोषण का शिकार होता रहा। बिचौलिए हमेशा हावी रहे। कभी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पाया। उद्योग घराने सरकारों से सांठगांठ कर किसानों का शोषण करते रहे।

भाजपा ने भी किसानों से बड़े-बड़े वादे किए लेकिन फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य देने, 2022 तक प्रत्येक किसान की आय दोगुना करने की दिशा में भाजपा सरकार ने अभी तक एक कदम भी नहीं बढ़ाया। भाजपा राज में जो तीन कृषि कानून आए हैं उसमें एमएसपी की गारंटी नहीं बल्कि मंडी व्यवस्था को समाप्त ,करने की

किसान कड़ाके की सर्दी में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष में दर्जनों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं लेकिन देश की कारपोरेट समर्थक सरकार हठधर्मी पर अड़ी है। केन्द्र की भाजपा सरकार किसानों के लिए पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है।

योजना है। किसान को खुले बाजार में बिचौलियों की दया पर छोड़ दिया गया है। फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं बीमा कंपनियों को ही मिल रहा है। किसानों को ऐसी एमएसपी चाहिए जिसमें किसान की आय दुगनी हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चौधरी चरण सिंह जी पूंजीवादी साजिशों को समझते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजस्व मंत्री के अपने कार्यकाल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर किसानों को ही मालिक बना देने के हक में बहुत बड़ा फैसला किया। चौधरी साहब आज भी देश में किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज पूरे देश का किसान उन्हें याद करता है। उनके कार्यों और उनकी नीतियों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गयी है। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों, किसानों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया।

चौधरी चरण सिंह जी का मत था कि गांवों के विकास के लिए प्रशासन तंत्र में कृषक परिवारों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति ही गांवो की समस्या और खेती की दिक्कतों को समझकर उसका निदान कर सकता है। वे मानते थे कि बड़े पैमाने पर तकनीक का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होना चाहिए। चौधरी साहब सही मायने में गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी गांव को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में उद्योग को कृषि के मुकाबले रियायतें दी थी। चौधरी साहब कृषि क्षेत्र की इस निरंतर उपेक्षा के चलते ही कांग्रेस के विरोधी बन गए थे। आज भाजपा सरकार किसानों को मार रही है। उनके साथ धोखा कर रही है। श्री अखिलेश जी स्वयं कृषक परिवार के होने के नाते जानते हैं कि कृषि का क्या महत्व है। उन्होंने अपने समय में कुटीर उद्योग हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया था।

चौधरी साहब 1937 में पहली बार विधायक चुने गये थे। बाद में श्री गोविन्द बल्लभ पंत के मंत्रिमण्डल में चौधरी साहब एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री संसदीय सचिव थे। वह आजादी के आंदोलन में अनेकों बार जेल गये। चौधरी चरण सिंह को 1951 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद प्राप्त हुआ। उन्होंने न्याय एवं सूचना विभाग संभाला। 1952 में डॉक्टर सम्पूर्णानंद के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें राजस्व तथा कृषि विभाग का दायित्व मिला। वह जमीन से जुड़े नेता थे और कृषि विभाग उन्हें विशिष्ट रूप से पसंद था। चरण सिंह जी स्वभाव से भी कृषक थे। वह कृषक हितों के लिए अनवरत प्रयास करते रहे। 1960 में चंद्रभानु गुप्त की सरकार में उन्हें गृह तथा कृषि मंत्रालय दिया गया। वह उत्तर प्रदेश की जनता के मध्य अत्यंत लोकप्रिय थे। इसीलिए प्रदेश सरकार में योग्यता एवं अनुभव के कारण उन्हें ऊंचा मुकाम हासिल हुआ।

चौधरी साहब आज भी देश में किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आज पूरे देश का किसान उन्हें याद करता है। उनके कार्यों और उनकी नीतियों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गयी है। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था।

उत्तर प्रदेश के कृषकों के कल्याण के लिए चौधरी साहब ने काफी कार्य किए। समस्त उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उनकी ईमानदाराना कोशिशों की सदैव सराहना हुई। वह लोगों के लिए एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा लोकप्रिय जननेता थे। उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा करती थी। चौधरी साहब 3 अप्रैल 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तब उनकी निर्णायक प्रशासनिक क्षमता की धमक और जनता का उन पर भरोसा ही था कि देश ही नहीं विदेश तक उनकी चर्चा हुई। उन्होंने अपने सिद्धांतों व मर्यादित आचरण से कभी समझौता नहीं किया। 'ऐन इंडियन पोलिटिकल लाइफ' पुस्तक के लेखक पाल आर ब्रास ने चौधरी साहब की बौद्धिकता की प्रशंसा करते हुए लिखा कि कृषि मूलक समस्याओं के अध्ययन में उन जैसा सुपठित नेता दूसरा नहीं है। उन्होंने तीन खंडो में चौधरी साहब की राजनीतिक जीवन यात्रा का जीवंत वर्णन किया है।

1977 में चुनाव के बाद जब केन्द्र में जनता पार्टी सत्ता में आई तो चरण सिंह जी को देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल व अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक ,नाबार्ड, की स्थापना की। चौधरी साहब ने तब कृषि यंत्रों पर उत्पाद शुल्क घटाया। खांडसारी की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक हटाई। खाद्य सब्सिडी में 25 प्रतिशत वृद्धि की। नाबार्ड की स्थापना की ताकि कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कर्ज मिल सके।

श्री अखिलेश यादव की प्राथमिकता में हमेशा खेती और किसान रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वे लगातार चिंतन करते हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने किसानों और गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलायी। गरीबों के लिए लोहिया ग्राम विकास और जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनाओं से गांव की दशा बदलने का प्रयास किया।

चौधरी चरण सिंह जी एक कुशल लेखक भी थे। उनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने 'इकोनामिक नाइट मेयर आफ इण्डिया इट्स काजेज ऐडं क्योर' अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लिजेण्ड प्रोपराइटरशिप और इंडियास पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशंस नामक कई पुस्तकों का लेखन भी अंग्रेजी में किया।

09 जनवरी 1959 को नागपुर में कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने सहकारी खेती का प्रस्ताव रखा था। तब नेहरू कांग्रेस के एक मात्र नेता थे और उनका दबदबा था लेकिन चौधरी साहब ने वहीं मंच पर उनका विरोध किया। फलस्वरूप नेहरू जी को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। आज फिर वही स्थिति है। भाजपा सरकार ने खेती पर किसान के स्वामित्व को समाप्त करने और कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर बड़े घरानों को मनमानी करने की छूट देने की साजिश की है।

आज चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर तथाकथित कृषि सुधार अधिनियम के विरूद्ध समाजवादी पार्टी संघर्षरत है। श्री अखिलेश यादव की प्राथमिकता में हमेशा खेती और किसान रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वे लगातार चिंतन करते हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने किसानों और गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलायी। गरीबों के लिए लोहिया ग्राम विकास और जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनाओं से गांव की दशा बदलने का प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दिया। दुग्ध के क्षेत्र में

कामधेनु योजना शुरू की।

किसानों को अपनी फसलों के विक्रय के लिए श्री अखिलेश यादव ने मंडियों की स्थापना की। लखनऊ आगरा-एक्सप्रेस-वे पर अनाज, फल और आलू एवं अन्य सब्जियों के लिए बड़ी-बड़ी मंडियों की स्थापना की। समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज, झांसी, बांदा, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, मैनपुरी, मलिहाबाद और ग्रेटर नोएडा आदि शहरों में कृषि मंडिया बनाई गईं थीं। लखनऊ, झांसी, सैफई, कन्नौज, बहराइच, मैनपुरी में किसान बाजार स्थापित किए गए थे। इनका उद्देश्य था कि फल-फूल, सब्जी, दूध सुगमता से दिल्ली जा सके और किसान को लाभप्रद मूल्य मिल सके।

फाइल चित्र

चौधरी चरण सिंह ने मंडी कानून अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मंडी कानून में कई परिवर्तन कराए थे। चौधरी साहब मानते थे कि कृषि में जो अतिरिक्त लोग लगे हैं उन्हें अन्य पेशों में लगाया जाना चाहिए जिनमें फल, सब्जी, दूध, मत्स्य पालन और ग्रामीण स्तर के परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग शामिल हैं। श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में चौधरी साहब के इस मंतव्य को वास्तविकता में अक्षरशः उतारा था।

समाजवादी सरकार ने प्रदेश में खेती योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए भूमि सेना योजना शुरू की थी। इस योजना में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर भूमिहीन किसानों को दिए जाने की व्यवस्था है। आज देश में सही मायनों में समाजवादी पार्टी ही अकेली पार्टी है जो किसानों और गांवों के उन्नयन के लिए समर्पित भाव से काम करती है। प्रदेश ही नहीं अपितु देश का किसान समाजवादी नेतृत्व पर भरोसा करता है। उत्तर प्रदेश के किसानों को श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व से ही न्याय मिलने का विश्वास है। किसान इस बात से आश्वस्त है कि समाजवादी सरकारों में कभी किसानों का अहित नहीं हो सकता। यह तो सभी महसूस करते हैं कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व की साख का प्रश्न है। अखिलेश जी की बेदाग छवि है। अपनी शालीनता, शिष्टता और लोकप्रियता में वे जनसामान्य में अलग प्रभाव रखते हैं। अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में प्रशासनिक कुशलता और विकास के प्रति समर्पण एवं पारदर्शिता के मामले में स्वयं एक उदाहरण है।

भाजपा के लिए किसान महज वोटबैंक

रविकान्त
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, लखनऊ विवि

किसानों की मांगों और उनके आंदोलन में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूंजीपति मित्र हैं तो दूसरी तरफ इस देश का सबसे बड़ा वर्ग खड़ा है। क्या मोदी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? देश का अन्नदाता किसान आज खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सर्दी में सोने के लिए मजबूर है। किसानों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा के लिए क्या किसान सिर्फ वोटबैंक है? 'किसान सम्मान निधि' देने वाली मोदी सरकार किसानों के नागरिक अधिकारों को क्यों नजरअंदाज कर रही है?

इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुई लोकलुभावन राजनीति का यह नया चलन है। गोया,मोदी सरकार मोदीराज में तब्दील हो गयी है। लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार हो रहा है। सरकारी खजाने को एक पार्टी या व्यक्ति की निजी संपत्ति की तरह दर्शाया जा रहा है। जनता के नागरिक-बोध और उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। एक अमूर्त राष्ट्रवाद के वास्ते जनता को आँख-नाक-कान और यहां तक कि जुबान भी बंद रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चुनी हुई सरकार के कामकाज की न तो कोई जवाबदेही है और ना ही कोई निगरानी। मोदी राज में विपक्ष होते हुए भी नहीं है।

अजीब बात है, जब किसी मुद्दे पर बहस होनी हो या कमेटी गठित होनी हो तो यह कहकर विपक्ष को खारिज कर दिया जाता है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी पार्टी के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है। लेकिन जब कोई जनांदोलन खड़ा होता है तो उसके पीछे विपक्ष की साजिश बताकर आंदोलन की विश्वसनीयता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। किसी आंदोलन के पीछे कोई है या नहीं है, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है या नहीं। सरकार उनकी आवाज को सुनती है या

नहीं।

दिल्ली के चारों तरफ जमा हजारों किसानों की मांगों पर सरकार कतई गंभीर नहीं लगती। 2014 और 2019 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी को समर्थन और वोट करने वाले किसानों की समस्याओं पर उनकी बेरुखी काबिले-गौर है। जब दिल्ली की ओर अपनी मांगों को लेकर बढ़ते किसानों पर इतने सर्द मौसम में दिल्ली और हरियाणा की पुलिस वाटर कैनन की बौछार कर रही थी, आँसू गैस के गोले दाग रही थी लगभग उसी समय नरेन्द्र मोदी काशी में देव दीपावाली के मौके पर नौकाविहार करते हुए भजन के रैप पर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। प्रधानमंत्री का यह रवैया केवल संवेदनहीनता ही नहीं, बल्कि चिढ़ाने जैसा था।

एक महीने से भी ऊपर से लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ठंड लगने से अब तक करीब दो दर्जन से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार और किसानों के बीच वार्ता के कई दौर नाकाम रहे हैं। किसानों की मांगें मानने

लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा व्यवहार हो रहा है। सरकारी खजाने को एक पार्टी या व्यक्ति की निजी संपत्ति की तरह दर्शाया जा रहा है। जनता के नागरिक-बोध और उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। एक अमूर्त राष्ट्रवाद के वास्ते जनता को आँख-नाक-कान और यहां तक कि जुबान भी बंद रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

का सरकार ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। सरकार कानून में आंशिक संशोधन करने के लिए तो तैयार है लेकिन उसकी तरफ से फसल के समर्थन मूल्य की गारंटी देने और कानूनों को रद्द करने की उसकी कोई मंशा नहीं दिखती है। इसलिए किसान भी अब आरपार के मूड में दिख रहे हैं।

किसान आंदोलन का नेतृत्व अधिकतर पंजाब के किसान और संगठन कर रहे हैं। इसलिए उनपर खालिस्तानी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। 70-80 के दशक में पंजाब में उभरा अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को बड़ी मुश्किल से समाप्त किया गया। इस आतंकवाद ने एक प्रधानमंत्री समेत हजारों बेकसूरों की जान ले ली। पंजाब उस अलगाववादी सोच से बाहर आ चुका है। ऐसे में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले किसानों को खालिस्तानी बताना बहुत खतरनाक है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि 'सिखों को खालिस्तानी कहना, आग से खेलना है।'

लेकिन सच यह है कि भाजपा और संघ इस खेल में माहिर हैं। किसी भी आंदोलन को बदनाम करना भाजपा की सोची-समझी रणनीति होती है। जेएनयू के आंदोलनकारी छात्रों को नक्सली, देशद्रोही और टुकड़ा-टुकड़ा गैंग कहा गया। जेएनयू की लड़कियों का चरित्र हनन किया गया। पुरस्कार वापस करने वाले लेखकों को पुरस्कार वापसी गैंग बताया गया। बुद्धिजीवियों और

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल बताकर उनका पैशाचीकरण किया गया। एनआरसी-सीएए विरोधी आंदोलन को पाकिस्तानी और आतंकवादी साजिश कहकर बदनाम किया गया। गोदी मीडिया और आईटी सैल की मिलीभगत से जनआंदोलनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की विश्वनीयता को ही कठघरे में नही खड़ा किया जाता बल्कि देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है।

मोदी सरकार द्वारा किसान आंदोलन से निपटने की क्रोनोलाजी को समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसे केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन कहा गया। यह भी कहा गया कि इसके पीछे विपक्षी दलों का हाथ है, लेकिन जब आंदोलन का स्वरूप बढ़ने लगा और कई राज्यों के विभिन्न समुदाय के किसान इससे जुड़ने लगे तो आंदोलन को खालिस्तानी साजिश कहकर बदनाम किया गया। भाजपा के दो मंत्रियों ने कहा कि यह आंदोलन पाकिस्तान और चीन के इशारे पर हो रहा है। भाजपा के नेता जब किसानों को बदनाम कर रहे थे, उसी समय सरकार किसानों से बातचीत कर रही थी। वार्ता के दरम्यान किसान नेताओं ने सरकार का 'नमक' भी नहीं खाया। वे अपना खाना-पानी साथ लेकर गए थे। अपनी मेहनत से 'रोटी' कमाने वाले किसान का स्वाभिमान अटूट है।

किसान आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका पंजाब के किसानों की है। सिख किसानों का एकजुट होकर संघर्ष करना देश को कमजोर करने की राजनीति नहीं है; जैसा कि गोदी मीडिया और भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सिख किसानों ने खेती को अधिक उन्नतशील बनाया है। पंजाब में कृषि व्यवस्था को बदलने का श्रेय बंदा बहादुर को जाता है। सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह ने नांदेड़ में बंदा बहादुर को अपना शिष्य बनाया। गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद बंदा बहादुर पंजाब आए। मुगलों और राजपूतों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने किसानों का जत्था तैयार किया। इसके बाद उन्होंने तेजी से अपनी सेना का विस्तार किया। उन्होंने जीती हुई जमीन को छोटी-छोटी जोतों में बांटकर भूमिहीनों को वितरित किया। 'जमीन, जोतने वाले की है' यह नारा बंदा बहादुर ने ही दिया था। बंदा बहादुर के विद्रोहों और जमीनों के वितरण से प्रभावित होकर तमाम हिन्दू और मुस्लिम गरीब किसानों ने सिख धर्म अपनाया। बंदा बहादुर द्वारा जमीनों के वितरण को, इतिहासकार दुनिया का पहला भूमि सुधार कार्यक्रम कहते हैं।

अपने पसीने से देश की समृद्धि की इबारत लिखने वाला किसान सर्द रातों में सड़क पर जूझने के लिए क्यों मजबूर है? दरअसल, महंगाई, भ्रष्टाचार दूर करने और किसानों को हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। करोड़ों किसानों को आशा थी कि नए भारत में उसकी भी नई तस्वीर होगी लेकिन पिछले पांच सालों में न तो उसकी तदबीर बदली और ना ही तकदीर।

आजादी के बाद देश में खाद्यान्न का विकट संकट था। पूरे देश को भुखमरी से निकालने में पंजाब के मेहनती किसानों की भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी सरकार में एम. एस. स्वामीनाथन के विशेष प्रयास से गेहूं और धान की अधिक उपजाऊ वाली फसलों को ईजाद किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खेती में आधुनिक और तकनीकी प्रयोगों से खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि अधिक पैदावार से सरकारी भंडारों को लबालब कर दिया है। खाद्यान्न की अधिकता से आज का भारत निर्यात करने में भी सक्षम हुआ है।

अपने पसीने से देश की समृद्धि की इबारत लिखने वाला किसान सर्द रातों में सड़क पर जूझने के लिए क्यों मजबूर है? दरअसल, महंगाई, भ्रष्टाचार दूर करने और किसानों को हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। करोड़ों किसानों को आशा थी कि नए भारत में उसकी भी नई तस्वीर होगी लेकिन पिछले पांच सालों में न तो उसकी तदबीर बदली और ना ही तकदीर। उल्टे डीजल और पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ी दरों से लेकर बिजली, खाद और बीज के दामों में बढ़ोतरी से किसान हलकान है। लेकिन इन तीन काले कानूनों के लागू होने से किसानों की जीविका ही छिन जाने का डर है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान (1936) के पात्र होरी की तरह वह किसान से मजदूर बनने के लिए अभिशप्त होगा। इसलिए वह अपने बाल-बच्चों के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए

तानाशाही सरकार के सामने डटकर खड़ा है।

हालांकि सरकार गतिरोध सुलझाने के बजाय किसानों से लड़ने के मूड में दिख रही है। तीनों काले कानून रद्द करने के बजाय भाजपा सरकार प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाएं आयोजित करके कानूनों के फायदे बता रही है। लगता है कि किसान आंदोलन को निपटाने की कमान खुद नरेन्द्र मोदी ने संभाल ली है। 25 दिसंबर को उन्होंने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रूपए किसान सम्मान निधि भेजने की बात कही है। इस ऐलान को मोदी ने एक बड़े ईवेंट में तब्दील कर दिया है। पूरे देश के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर नरेन्द्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण किया गया। इस ईवेंट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। टीवी और अखबारों में भी करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर इन कानूनों के फायदे बताए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की बात सरकार के कानों में नहीं धंस रही है। अब हालात यह हैं कि एनडीए में शामिल कई राजनीतिक दलों ने किसानों के समर्थन में नरेन्द्र मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है। सबसे पहले पंजाब की अकाली दल ने साथ छोड़ा। भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में अकाली दल आता है। अभी राजस्थान के जाट नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी बगावत कर दी है। बेनीवाल ने लोकसभा की तीन कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। इतना ही नहीं भाजपा के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने भी किसानों की माँगों का समर्थन किया है। लेकिन मोदी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है।

किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा के किसानों के साथ अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है लेकिन भाजपा शासित राज्यों का प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को बर्बरतापूर्वक रोका जा रहा है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।

सपा गांवों और कस्बों में किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। इससे सपा को भी किसानों और अन्य वर्ग का भी साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव ने जता दिया है कि वे किसानों के हक में खड़े रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसानों की मांगों और उनके आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सड़क पर आकर किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस ने अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। लेकिन सपा के कार्यकर्ता न डिगे और न डरे। अब सपा गांवों और कस्बों में किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। इससे सपा को भी किसानों और अन्य वर्ग का भी साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव ने जता दिया है कि वे किसानों के हक में खड़े रहेंगे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों के आंदोलन की चर्चा हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री और अमेरिका के कई सांसद किसानों के समर्थन में बयान जारी कर चुके हैं। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ,इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीयों ने प्रदर्शन किए हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और नरेन्द्र मोदी की छवि खराब हुई है। पूंजीपतियों के फायदे के लिए नरेन्द्र मोदी किसानों की जमीनों का सौदा करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। किसानों को बरगलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान जानते हैं कि ये कानून सायनाइड हैं। इसलिए वे इसे नहीं चखना चाहते। इस बार लड़ाई अन्नदाता से है। चंपारन सत्याग्रह (11अप्रैल, 1917) के 103 साल बाद, तय होगा कि स्वराज करोड़ों किसानों का है या मुट्ठी भर पूंजीपतियों का?

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

वर्चुअल रैली से समाजवादियों ने किया संवाद

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 21 दिसंबर को संतकबीरनगर में हुई वर्चुअल रैली को संबोधित किया। श्री यादव ने रैली के संयोजक श्री सुनील सिंह की गिरफ्तारी को अवैध और निंदनीय बताते हुए कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने से बाज आए। भाजपा का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। हिरासत में मौतों और फर्जी एनकाउण्टरों पर मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को कई नोटिसें जारी कर चुका है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा किसानों को डराना चाहती है, पर किसान डरने वाला नहीं है। तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी उनके संघर्ष में साथ है। भाजपा जो कानून लाई है वह किसान

विरोधी है और उससे कुछ पूंजीपतियों को ही लाभ मिलेगा। इस सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी परेशान है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से पूरे देश में बदनामी हो रही है। नौजवानों को नौकरी मिली नहीं। 4 लाख करोड़ का निवेश कहा हुआ, पता नहीं। गोरखपुर में एम्स अभी तक बन नहीं पाया। भाजपा सरकार अब अंतिम सांसे ले रही है। जनता का सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ है। सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के साथ भाजपा ने बड़ा धोखा किया है। एमएसपी मिली नहीं। आय दुगनी हुई नहीं। धान की कीमत 1100 रुपये से ज्यादा नहीं मिली। क्रय केंद्रों में खरीद नहीं हो रही है। लागत का ड्योढ़ा दाम भी नहीं मिला। किसान को महंगी खाद, डीजल, कृषि उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। धान की लूट हुई है। गन्ना किसानों को 4 वर्ष में भी बकाया राशि नहीं मिली। बिजली मंहगी है।

भाजपा सरकार ने अपने शासन काल में एक यूनिट विद्युत उत्पादन नहीं किया। रोजगार नहीं है। कारखाने बंद हैं। विकास कार्य धुआं हो गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय को किसानों से कोई मतलब नहीं है।

अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने शासन काल में एक यूनिट विद्युत उत्पादन नहीं किया। रोजगार नहीं है। कारखाने बंद हैं। विकास कार्य धुआं हो गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय को किसानों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार जाति के आधार पर निर्णय लेती है। झूठे मुकदमें लगाती है। बदले की भावना से उत्पीड़न करती है। समाजवादी नेताओं को जेल में रखकर द्वेषवश पीड़ित किया जाता है। समाजवादी झुकने या डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी अन्याय के विरूद्ध संघर्षरत है।

रैली को संबोधित करते हुए किसान नेता

9415692349

9415692349
ANIS

वर्चुअल रैली कार्यक्रम में लखनऊ से श्री अखिलेश यादव के साथ नेता विपक्ष विधानसभा श्री रामगोविन्द चौधरी, नेता विपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन तथा राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी शामिल हुए। वर्चुअल रैली में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर और गोरखपुर के भी कई नेता जुड़े। इस संवाद में सर्वश्री रामप्रसाद चौधरी, जफर अमीन डक्कू, संतोष यादव सनी, रामकुमार चिंकू, रामललित चौधरी, पप्पू निषाद एवं अब्दुल कलाम पूर्व विधायक, सुरेन्द्र यादव, अवधेश यादव, जयराम पाण्डेय, ओम प्रकाश यादव, राधे सिंह सेतवार, नगीना साहनी, इनामुल्ला खां एडवोकेट, मनोज यादव, महेन्द्र यादव, विजय बहादुर, सद्दाम हुसैन, नावेद नवी, अरशद हुसैन, अमरेन्द्र निषाद आदि शामिल रहे। गौहर खान जिलाध्यक्ष संतकबीरनगर ने संचालन किया।

अम्बिका राय ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव पर कोई लांछन नहीं, उनकी छवि बेदाग नेता की है। इस बार कोई भी ताकत अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकेगी। अन्य लोगों ने कहा कि भाजपा किसान की जमीन छीनने की साजिश कर रही है। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी पर है।

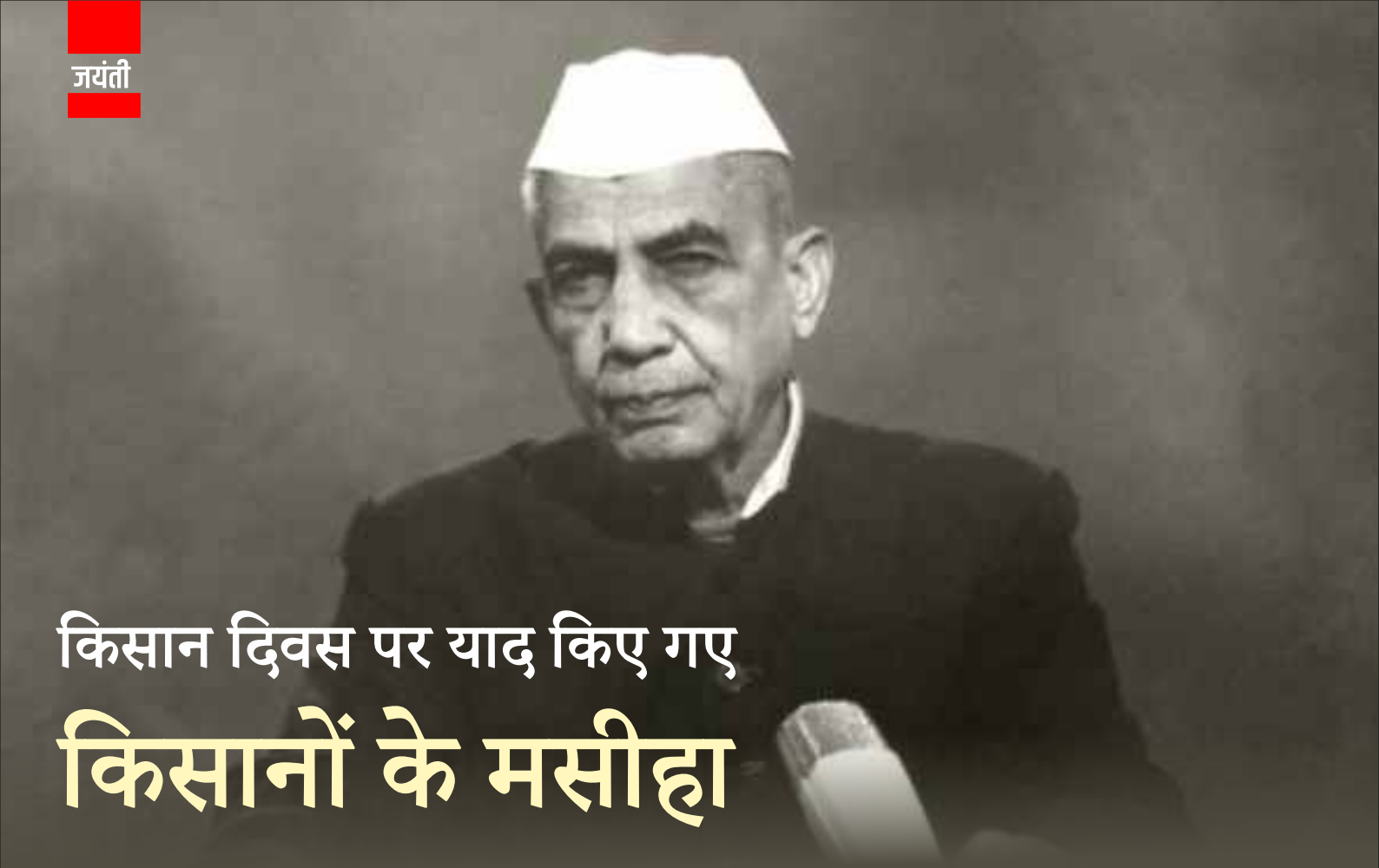

किसान दिवस पर याद किए गए
किसानों के मसीहा

बुलेटिन ब्यूरो

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का 118 वां जन्म दिवस 23 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ने 'किसान दिवस' के रूप में मनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं-नेताओं ने उनका नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि दी। प्रत्येक जनपद में इस अवसर पर चौधरी साहब के राजनीतिक योगदान की चर्चा की गई और किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कामों का स्मरण किया गया।

समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। उन्होंने चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प दिलाया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी भी साथ में मौजूद थे। इस अवसर पर सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राजधानी में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी स्थित चौधरी साहब की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है, जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े! क्योंकि देश का किसान भारत का मान है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का गांव-किसान से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वह तो कारपोरेट की पोषक है। इन दिनों किसानों के आक्रोश को देखते हुए वह चौधरी साहब के प्रति दिखावटी सम्मान प्रदर्शित करते बड़े-बड़े सरकारी विज्ञापनों में स्मरण की निरर्थक कवायद कर रही है। चौधरी साहब के प्रति यह पहली बार स्नेह उमड़ा है। चौधरी साहब की बड़ी फोटो लगाने का क्या अर्थ जबकि भाजपा का दिल ही बड़ा नहीं है। वैसे भी सरकार यह न समझे कि चौधरी साहब के नाम पर धूमधड़ाका करके किसानों की आवाज को वह दबा सकेगी या उनमें भ्रम फैला देगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा

सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती है। वह किसानों को डराने-धमकाने में लगी है। भाजपा का किसान विरोधी आचरण चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता नहीं कृतघ्नता ही प्रदर्शित करता है। चौधरी साहब के नाम पर किसान सम्मान जैसा आडम्बर चलने वाला नहीं है। भाजपा की विरोधाभासी नीतियों से कोई अब गुमराह करने की कोई साजिश सफल नहीं होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि धान-गन्ना की अपनी ही कमाई के लिए किसान भटक रहे है। एमएसपी का अता पता नहीं। क्रय केंद्रों पर भी किसान को परेशान किया जाता है। समय से भुगतान भी नहीं होता है। किसान के साथ जो वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं किए गए। उल्टे तीन कृषि कानून लाकर उनकी खेती कारपोरेट को बेचने की तैयारियां की जा रही है। कंपकंपाती ठंड में किसान सड़कों पर है और इसको वापस लिए जाने की मांग कर रहे है जिसमें दो दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हो गए है। फिर किस मुंह से भाजपा अपने को किसान हितैषी बता रही है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की आर्थिक नीतियां वही हैं जो चौधरी साहब की रही हैं। उन्होंने केंद्र में वित्तमंत्री रहते बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों को दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कुल बजट का 75 प्रतिशत गांव-खेती के लिए देकर उनका अनुसरण किया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। किसानों के लिए मंडी व्यवस्था और सहकारिता क्षेत्र को मजबूती दी। किसानों को समय से कर्ज, खाद-बीज उपलब्ध कराया। गन्ना किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया।

अखिलेश जी ने कहा कि चौधरी साहब ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर किसानों को भूमिधर बनाया। भूमि संरक्षण कानून लागू किया। चौधरी साहब मानते थे कि किसानों की खुशहाली से ही देश खुशहाल होता है। चौधरी साहब का कहना था कि खेतों से किसानों के स्वाभाविक लगाव की वजह से देश में सहकारी खेती सफल नहीं होगी। चौधरी साहब की सामाजिक नीतियों में जातिवाद का तीखा विरोध था। नौकरियों में इसकी अनिवार्यता पर वे बल देते थे। समाज में वे सामाजिक समरसता के हिमायती थे।

समाजवादी पार्टी की आर्थिक नीतियां वही हैं जो चौधरी साहब की रही हैं। उन्होंने केंद्र में वित्तमंत्री रहते बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों को दिया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने कुल बजट का 75 प्रतिशत गांव-खेती के लिए देकर उनका अनुसरण किया था।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना का चौधरी चरण सिंह के प्रयासों को समाजवादी गति देने का संकल्प लेकर चल रहे है। भाजपा को न किसानों की चिंता और नहीं बेरोजगार नौजवानों की फिक्र है। भाजपा की पहली ऐसी सरकार है जिसने चार वर्षों में कोई काम नहीं किया है। झूठ, अफवाह और नफरत की भाजपा राजनीति को देश स्वीकार्य नहीं करेगा।

मनीषियों को नमन

बाबा साहब एवं संत गाडगे को श्रद्धांजलि

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी मुख्यालय में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस एवं संत गाडगे बाबा की 64वीं पुण्यतिथि श्रद्धा से मनाए गए।

बाबा साहब के परिनिर्वन दिवस 6 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने डाॅ अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में सामाजिक बुराइयों से लड़ने वालों में डाॅ अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर है। उन जैसा दूसरा समाज सुधारक नहीं मिलेगा। उनका रास्ता कठिनाइयों से भरा था फिर भी उन्होंने गरीब और दलित को सम्मान दिलाया, संविधान में सबको एक वोट का अधिकार दिया

जिससे जिनको अछूत माना जाता था उन्हें भी बराबरी और सुरक्षा की गारंटी मिली।

श्री यादव ने कहा कि करोड़ों लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं। समाजवादी पार्टी हर वर्ष बाबा साहब की जन्म तिथि पर और परिनिर्वाण दिवस पर बड़ा आयोजन करती है। उन्होंने कहा आज जो माहौल है उसमें नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। भाजपा की राजनीति से दलितों, पिछड़ों को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। नौकरी और पढ़ाई में भी बाधा आएगी। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि सब मिलकर डा॰ अंबेडकर का रास्ता अपनायें। हमें जो राजनीतिक अधिकार मिले हुए है यह उनकी ही देन है। उनके द्वारा संविधान में अंकित लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को जब हम अपना कर चलेंगे तभी हमारा सम्मान एवं हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी की रहनुमाई में ही दलितों, वंचितों के सम्मान की लड़ाई जीती जा सकेगी। वे मुख्यमंत्री होंगे तो समाज के कमजोर असहाय और वंचितों का जीवन में भी खुशहाली आएगी।

आज जो माहौल है उसमें नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। भाजपा की राजनीति से दलितों, पिछड़ों को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। नौकरी और पढ़ाई में भी बाधा आएगी। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि सब मिलकर डॉ अंबेडकर का रास्ता अपनायें।

दिनांक 20 दिसंबर को संत गाडगे बाबा की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बाबा के समाज सुधार आंदोलन से प्रेरणा लेने को कहा। अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध के साथ शिक्षा, स्वच्छता और लोक शिक्षण की दिशा में उनके अप्रतिम योगदान के अनुकरण पर भी उन्होंने बल दिया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि संत गाडगे निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने-कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। यह सब उन्होंने लोगों से सहयोग लेकर बनाया लेकिन अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई।

विधान परिषद चुनावों में लहराया समाजवादी झंडा

बुलेटिन ब्यूरो

विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वाराणसी से शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री लाल बिहारी यादव, झांसी खंड स्नातक सीट पर डा॰ मान सिंह यादव तथा वाराणसी सीट पर श्री आशुतोष सिन्हा ने जीत दर्ज की है। श्री मान सिंह यादव ने चार बार के भाजपा विधायक श्री यज्ञदत्त शर्मा को पराजित किया। श्री आशुतोष सिन्हा ने निवर्तमान विधायक केदार नाथ सिंह को शिकस्त दी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक सीट तथा झांसी-प्रयागराज खण्ड स्नातक सीट पर जीते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया है।

22 में
सिकल

विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत और अपनी हार से बौखलाए भाजपाइयों ने मतगणना में घपले की कोशिश में झांसी की पुलिस पर जानलेवा हमला तक किया। इसी तरह आगरा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के विरूद्ध सरकारी तंत्र साजिशों से बाज नहीं आया। हजारों मतपत्र मनमाने तरीके से रद्द कर दिए गए ताकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हार हो जाए। इन तरीकों से भाजपा के जीत के दावे अनैतिक और अवांछनीय है।

शिक्षक स्नातक चुनावों में सत्ता के खुले दुरुपयोग व फर्जीवाड़े के बाद भी झांसी से लेकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने भाजपा नेतृत्व को बता दिया है कि अब भाजपा से उसका विश्वास उठ गया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति किसान तो आंदोलित हैं ही शिक्षक, स्नातक भी उनको सबक सिखाना चाहता है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 9 दिसंबर को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री आशुतोष सिन्हा एवं डा॰ मान सिंह तथा शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री लाल बिहारी यादव ने भेंट कर विधायिका में सेवा का अवसर देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उम्मीद जाहिर की कि विधान परिषद में समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को वे मुखरता से उठाएंगे और स्नातकों तथा शिक्षकों के मसलों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का काम करेंगे।

श्री यादव ने प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में दो समाजवादी प्रत्याशियों की जीत को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ईवीएम मशीन पर बैलेट पेपर की जीत हुई। भाजपा मशीन से चुनाव जीतने की साजिश करती है। इस सबके बावजूद यह मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसे की जीत है। श्री यादव ने कहा कि सन् 2022 के विधानसभा चुनावों में अब देर नहीं। सन् 22 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी है। सभी को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तरह काम करना है।

समाजवादी पार्टी द्वारा श्री आशुतोष सिन्हा को स्नातक क्षेत्र से विजयी बनाकर विधान परिषद सदस्य बनाने से उल्लसित कायस्थ समाज के लोगों ने 10 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज को

2022 के विधानसभा चुनावों में अब देर नहीं। सन् 22 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी है। सभी को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तरह काम करना है।

सम्मान देकर उन्हें अपना बना लिया है। कायस्थ समाज के महापुरुषों डाॅ राजेन्द्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति को यादगार बनाने का समाजवादी पार्टी ने ही प्रयास किया है। राजधानी लखनऊ में जेपी इंटरनेशनल सेंटर जैसी ऐतिहासिक इमारत समाजवादी सरकार ने बनाई जिसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया है।

कायस्थ समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कायस्थ समाज के सहयोग से प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से श्री आशुतोष सिन्हा की जीत बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सन्2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए आज से ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। चुनाव में बहकाने वालों से सतर्क रहकर मतदान करना है। यह याद रखना चाहिए कि भाजपा षड़यंत्र करने में उस्ताद है। वह झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति करती है। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी ही विकास का काम कर सकते हैं। जनता समझने लगी है कि समाजवादी सरकार से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता है। भाजपा को भी लग रहा उनके निकम्मेपन के कारण प्रदेश में अगले चुनावों में उसका सफाया होना सुनिश्चित है।

यूपी सरकार का युवा विरोधी कानून

अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने में रोड़े

ऋचा सिंह

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद केंद्रीय विवि

एक तरफ़ बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई, रसातल में जाती अर्थव्यवस्था, महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा,कृषि बिल पर अपनी ही सरकार से जूझता देश का किसान और दूसरी तरफ़ इन समस्याओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020" को आनन फ़ानन में क़ानून के रूप में मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के निशाने पर एक बार फिर से संविधान और एक विशेष समुदाय है।

गौरतलब है कि अध्यादेश पास करने की शक्ति कार्यपालिका को विशेष परिस्थितियों में दी गयी है, जब किसी विषय पर कोई गंभीर कानूनी शून्यता पैदा हो जाये, या इमरजेंसी जैसे हालात हों, सामान्य परिस्थितियों में नहीं। पर वर्तमान में ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति उत्तर प्रदेश सरकार के सामने दिखायी नहीं पड़ती सिवाय राजनीतिक एजेंडे के!

उल्लेखनीय है कि अध्यादेश में उल्लेखित समस्याओं के निवारण के लिए पहले से ही "स्पेशल मैरिज एक्ट , आई.पी.सी, सी.आर.पीसी में पर्याप्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।

दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब भारत का संविधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता- स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीवन को मूलभूत अधिकार का दर्जा देता है तो कोई भी अध्यादेश या कानून जो संविधान की मूल भावना

के विपरीत हो उसे सरकार द्वारा कैसे पास किया जा सकता है ।

तीसरा, यह भी गौरतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने एक फैसले में अवधारित किया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के तहत आता है , चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म अथवा जाति का हो (सलामत अंसारी एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया)

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश के आने के साथ ही इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में इस अध्यादेश को गैरजरूरी बताया गया है और कहा गया है कि यह सिर्फ सियासी फायदे, समाज में मतभेद और विभिन्न वर्गों में खाई पैदा करने के लिए है, जिससे एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा सकता है ! याचिका में यह भी दलील दी गई है कि यह अध्यादेश संविधान के अंतर्गत लोगों को मिले मौलिक अधिकार के खिलाफ है इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब- तलब भी किया है।

अध्यादेश के दुष्परिणाम

अभी जब अध्यादेश को आये कुछ चंद दिन ही हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री और नेता इस अध्यादेश के नाम पर वर्ग विशेष को टारगेट कर अनर्गल बयानबाजी से समाज का माहौल खराब करने का प्रयास करते हुए सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं ,ऐसे में इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020"

यह सिर्फ सियासी फायदे, समाज में मतभेद और विभिन्न वर्गों में खाई पैदा करने के लिए है, जिससे एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा सकता है !

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध धर्मांतरण कानून के नाम पर महिला प्रताड़ना की घटना सामने आई है। जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि इस कानून के नाम पर मुकदमा दर्ज कर उसके पति को जेल भेज दिया गया और उसे नारी निकेतन, जहां उसका जबर्दस्ती गर्भपात करवा दिया गया । यह इस गैर ज़रूरी क़ानून का बेहद स्याह पक्ष है।

एक अन्य ताजा उदाहरण है जहां पुलिस ने बीते आठ दिसंबर को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा 'लव जिहाद' की अफवाहों के आधार पर एक मुस्लिम युवक-युवती को शादी करने से रोक दिया। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का है। जहां पुलिस ने उन्हें पीटा, प्रताड़ित किया और रात भर हिरासत में रखा।

कुछ ऐसा ही मामला कुशीनगर में पहले भी सामने आ चुका है जहां लव जिहाद का मामला बनाने की कोशिश करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गयी। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने ना सिर्फ एफ आई आर खारिज कर दी बल्कि सख्त प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगायी और कहा कि "न्यायालय और संवैधानिक अदालतों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने का दायित्व है"

हाईकोर्ट ने अपने 14 पन्नों के आदेश में कहा,

" अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ जीवन

विवादित कानून से असहमति

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश सरकार के विवादित कानून से युवाओं में असहमति है। इस कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमएससी की छात्रा प्रियंका का कहना है " सिर्फ धर्म के नाम पर किसी भी क़ानून का समर्थन नहीं किया जा सकता है, यह क़ानून व्यक्तिगत संवेदनाओं को बाधित करने और मौलिक अधिकारों से वंचित करने की ओर एक क़दम है।"

विश्वविद्यालय की शोध छात्रा प्रीति त्रिपाठी का कहना है कि "जब उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी की विकराल समस्या से जूझते हुए आत्महत्या जैसे घातक क़दम उठाने पर मजबूर है, ऐसे में सरकार द्वारा युवाओं के व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला, उत्तर प्रदेश सरकार के साम्प्रदायिक चेहरे का पर्दाफाश करता है।"

महिला अधिकारों के लिये काम करने वाली डॉ पद्मा सिंह कहती हैं - " इस तरह का क़ानून महिलाओं की आज़ादी पर हमला है, शादी जैसे फैसले किसी भी महिला के नितांत निजी फैसला है, जिसमें किसी भी तरह से राज्य को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।

व्यतीत करना चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो हर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है"

सामाजिक जनतंत्र पर हमला

इस तरह का क़ानून सामाजिक जनतंत्र पर हमला है। अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना सामाजिक जनतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है।

गौरतलब है कि सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सामाजिक जनतंत्र पर लगातार संगठित हमले कर रही है, इसी क्रम में युवाओं की अपनी पसंद के जीवन साथी चुनने के अधिकार पर सरकार का यह हमला है । भाजपा समाज में

इस तरह के मुद्दे आज भाजपा की राजनीति की जरूरत है क्योंकि वह समाज को धर्म जाति के खांचों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। एक तरफ वह धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे है और दूसरी तरफ स्त्री-पुरुष के बीच असमानता को सामाजिक ठेकेदारी के नाम पर पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जहां दो वयस्कों की आपसी सहमति या निर्णय जो बेहद व्यक्तिगत है वह राज्य सरकारों की दया या सहमति पर निर्भर करने जैसा है और व्यक्तिगत आजादी में दखलअंदाजी है।

दरअसल इस तरह के मुद्दे आज भाजपा की राजनीति की जरूरत है क्योंकि वह समाज को धर्म जाति के खांचों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। एक तरफ वह धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे है और दूसरी तरफ स्त्री-पुरुष के बीच असमानता को सामाजिक ठेकेदारी के नाम पर पोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान में लिखे वाक्य "भारत एक धर्मनिरपेक्ष -

पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है" को झुठला रही है और संविधान की आत्मा पर हमला कर रही है, वास्तव में इस तरह की धर्म आधारित राजनीति अल्पसंख्यकों पर दमन की राजनीति है।

बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि "भारत से छुआछूत, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने और धर्मिक सौहार्द के लिये इनके विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये" एक तरफ बीजेपी दलितों के वोट के लिये दलित-शोषित समाज को गुमराह करती है, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों को मानने के लिये तैयार नहीं है।

असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश

मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र की जड़ों को कमजोर कर देने के बाद सामाजिक जनतंत्र को समाप्त करने की दिशा में धर्मान्तरण अध्यादेश एक कदम है। सामाजिक जनतंत्र बना रहे इसके लिए संविधान का शासन है और विधि की व्यवस्था बनी हुई है पर भारतीय जनता पार्टी न संविधान का आदर करती है ना विधि की व्यवस्था को मानती है।

ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के चलते करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं , बेरोजगारी पिछले 3 दशकों में अपने चरम पर है, जीडीपी में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, अर्थव्यवस्था खतरे में है, प्रवासी मजदूर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, बच्चे बाल मजदूरी की ओर अग्रसर हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, किसान सड़को पर अपनी ही चुनी हुई सरकार से संघर्षरत है तब इस तरह के अध्यादेश से सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाना चाहती है।

एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना, दो वयस्कों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण है।

भारत आज सबसे युवा देश है, और कानून के जरिए मूलभूत अधिकारों पर बंदिशे लगाने के परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। शादी - विवाह व्यक्तिगत आजादी का मसला है जिस पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया कानून संवैधानिक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और अपनी इच्छाओं को कानून घोषित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का यह विवादास्पद अध्यादेश अदालत में है और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

भारत आज सबसे युवा देश है, और कानून के जरिए मूलभूत अधिकारों पर बंदिशे लगाने के परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। शादी - विवाह व्यक्तिगत आजादी का मसला है जिस पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया कानून संवैधानिक नहीं है।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

रामपुर के सांसद आज़म खान जी की पत्नी तज़ीन फ़ातिमा जी की ज़मानत ने साबित कर दिया है कि नफ़रत की सियासत करनेवाले आख़िर में सच के आगे हारते हैं. भाजपा झूठ के जिस रास्ते पर चल रही है वो अन्याय की ओर जाता है और पतन की ओर ले जाता है.

ये इंसाफ़ में एतबार करनेवालों की जीत है.

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

जिस प्रकार हाथरस कांड में भाजपा सरकार के झूठ की पोल खुली है उससे उप्र में झूठे मुक़दमों की कलई खुलनी शुरू हो गयी है। न्यायपालिका व लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आज़म ख़ान साहब के झूठे मुक़दमे भी हारेंगे और उन्हें बहुत जल्द इंसाफ़ मिलेगा।

#नहीं_चाहिए_भाजपा

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

आज प्रदेश भर में काले कृषि क़ानूनों के विरोध में सपा द्वारा आयोजित 'किसान-घेरा' कार्यक्रम में लाखों किसानों ने भागीदारी कर जता दिया है कि भाजपा लाख झूठ बोले पर वो समझ गये हैं कि कृषि-क़ानून एक बड़ा छलावा हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सपा के हर नेता एवं कार्यकर्ता को बधाई!

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा सरकार सड़क पर बैठे अपने अधिकार के लिए लड़ते किसानों का अपमान कर रही है व 'किसान सम्मान' की नाममात्र की राशि की आड़ में काले कृषि-क़ानून लागू कर उनका हज़ारों-लाखों का नुक़सान करना चाहती है।

सत्ता के अहंकार में भाजपा किसानों व देश के हर नागरिक की थाली का भी अपमान कर रही है।

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

बेरोज़गारी के इस भीषण दौर में आधे से अधिक अभ्यर्थियों का परीक्षा में अनुपस्थित रहना चिंता का विषय है। इसके पीछे कोरोना के दौर में ध्वस्त परिवहन व्यवस्था है या महामारी की आशंका या भाजपा सरकार से युवाओं की नाउम्मीदगी। युवाओं के इस गंभीर प्रश्न पर प्रदेश की भाजपा सरकार जवाब दे।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली करने के लिए कोरोना नहीं है, तो संसद सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यों है। संसद में किसानों के पक्ष में जन प्रतिनिधियों के आक्रोश से बचने के लिए भाजपा सरकार कोरोना का बहाना बना रही है।

भाजपा संसदीय-सांविधानिक परंपराओं का क़त्लेआम कर रही है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Salute to our brave heroes of the Indian Armed Forces on the historic occasion of #VijayDiwas - India's win over Pakistan in 1971 War that led to the liberation of Bangladesh. My humble tributes to the martyrs. Jai Hind! 🇮🇳

@adgpi
@IAF_MCC
@indiannavy

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा के 'दमनकारी राज' के बावजूद किसानों के समर्थन में संत कबीर नगर में सपा की वर्चुअल रैली सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। रैली के आयोजक की गिरफ़्तारी की पूरे प्रदेश में घोर निंदा हो रही है।

दमन का बढ़ना सत्ता के निरंतर कमज़ोर होने का प्रतीक होता है।

#नहीं_चाहिए_भाजपा

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या LW/NP-300/2018-2020

बंधनमुक्त अन्नदाता

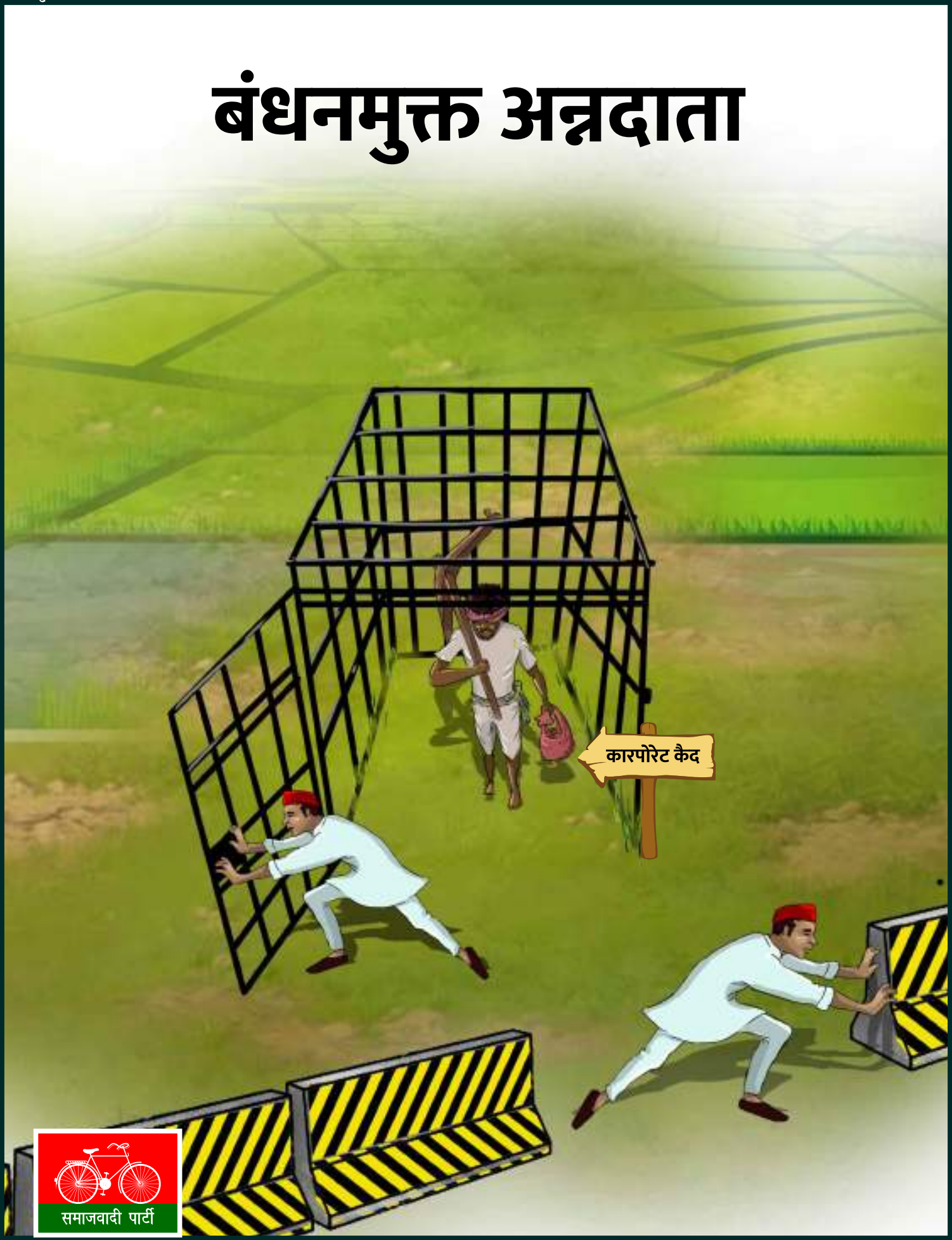

समाजवादी पार्टी

www.samajwadiparty.in